भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 530

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

29 आषाढ़, 1944 (शक)

आधार संख्या

530. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आम तौर पर पूरे देश में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें यूआईडीएआई द्वारा अभी भी आधार संख्या जारी किया जाना बाकी है;

(ख) इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और गैर-शामिल लोगों को कवर करने के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या बिना हाथों या स्पष्ट उंगलियों के निशान वाले नागरिकों के बारे में कोई डेटा है, जिन्हें अभी भी आधार संख्या जारी नहीं की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिना हाथ वाले या बिना स्पष्ट उंगलियों के निशान वाले लोगों के लिए आधार संख्या जारी करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : आरजीआई डेटा के अनुसार, भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या (2022) 137.30 करोड़ (लगभग) है। 30 जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 133.586 करोड़ आधार तैयार किए गए हैं । हालांकि, मृत्यु के कारण आधार धारकों की वास्तविक संख्या कम होगी । इसलिए, जीवित आधार धारकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए "लाइव आधार " की अवधारणा पेश की गई है । अनुमान है कि लाइव आधार की संख्या 127.79 करोड़ है । इस सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लगभग 9.51 करोड़ की आबादी द्वारा आधार के लिए नामांकन करना अभी भी बाकी है, जिनमें से 8.30 करोड़ 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश की कुल अनुमानित जनसंख्या (2022) 8.55 करोड़ (लगभग) है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में लाइव आधार का अनुमान 7.63 करोड़ (लगभग) है । यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लगभग 92.01 लाख की आबादी द्वारा आधार के लिए नामांकन करना अभी भी बाकी है, जिनमें से 67.29 लाख 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं।

30 जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार आधार संतृप्ति रिपोर्ट **अनुबंध -I** के रूप में संलग्न है ।

(ख) : यूआईडीएआई ने निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रार के रूप में डाक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, नवोदय विद्यालय समिति, बीएसएनएल, सीएससी, यूटीआईआईटीएसएल,

आईपीपीबी आदि सहित विभिन्न केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों को ऑन बोर्ड किया है । इसके अलावा, यूआईडीएआई अपने सेवा प्रदाताओं के माध्यम से देश भर के चुनिंदा शहरों में आधार सेवा केंद्र (एएसके) को स्थापित करने और प्रचालन की प्रक्रिया में है ।

यूआईडीएआई आधार के लिए छूटी हुई आबादी को शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 30 जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 57,000 आधार काउंटर प्रचालनरत थे। इसके अलावा, लगभग 34,000 मोबाइल/टैबलेट आधारित चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) भी विशेष रूप से 0-5 आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन के लिए कार्य कर रहे हैं।

(ग) : यूआईडीएआई से संपर्क करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आधार जारी किया गया है, भले ही निवासी के हाथ या स्पष्ट उंगलियों के निशान न हों।

(घ) : आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6(1) में प्रावधान किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि - " चोट, विकृति, उंगलियों/हाथों के विच्छेदन या किसी अन्य प्रासंगिक जैसे कारणों से उन निवासियों के लिए जो उंगलियों के निशान प्रदान करने मे असमर्थ हैं, ऐसे निवासियों के केवल आईरिस स्कैन एकत्र किए जाएंगे"।

आम जनता के संदर्भ के लिए सूचना, यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है । इसके अलावा ,बायोमेट्रिक अपवाद दिशानिर्देश भी उपलब्ध कराये गए हैं और ये fdp.2014-08-01_senilediug_noitpecxe_cirtemoiB/segami/ni.vog.iadiu//:sptth लिंक पर उपलब्ध हैं-:

******

अनुबंध- I

30 जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आधार संतृप्ति				
क्रमांक	**राज्य का नाम**	**कुल जनसंख्या (अनुमानित 2022)***	**सौंपे गए आधार की संख्या (लाइव)**	**संतृप्ति% (लाइव)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,02,000	3,85,820	95.98%
2	आंध्र प्रदेश	529,72,000	514,79,040	97.18%
3	अरुणाचल प्रदेश	15,48,000	12,38,995	80.04%
4	असम	353,78,000	298,19,791	84.29%
5	बिहार	1249,19,000	1072,06,477	85.82%
6	चंडीगढ़**	12,19,000	11,48,951	94.25%
7	छत्तीसगढ	298,36,000	278,40,763	93.31%
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव **	6,44,174	5,96,417	92.59%
9	दिल्ली	209,65,000	224,25,340	106.97%
10	गोवा	15,67,000	16,08,638	102.66%
1 1	गुजरात	706,48,000	646,47,666	91.51%
12	हरियाणा	298,46,000	298,31,817	99.95%
13	हिमाचल प्रदेश	74,31,000	76,89,079	103.47%
14	जम्मू कश्मीर	135,05,000	115,68,584	85.66%
15	झारखंड	389,69,000	352,12,564	90.36%
16	कर्नाटक	672,68,000	639,71,673	95.10%
17	केरल	356,33,000	370,12,332	103.87%
18	लद्दाख	2,99,000	2,34,182	78.32%
19	लक्षद्वीप	68,000	73,170	107.60%
20	मध्य प्रदेश	855,48,000	763,46,715	89.24%
21	महाराष्ट्र	1254,11,000	1165,78,452	92.96%
22	मणिपुर	31,94,000	25,84,549	80.92%
23	मेघालय	33,18,000	20,75,848	62.56%
24	मिजोरम	12,27,000	11,62,850	94.77%
25	नगालैंड	22,13,000	13,29,441	60.07%
26	उड़ीसा	441,62,000	434,77,548	98.45%
27	पुडुचेरी **	13,62,786	12,83,443	94.18%
28	पंजाब	305,35,000	309,01,120	101.20%
29	राजस्थान	801,53,000	738,86,696	92.18%
30	सिक्किम	6,83,000	5,73,858	84.02%
31	तमिलनाडु	766,31,000	736,51,371	96.11%
32	तेलंगाना	379,07,000	380,68,389	100.43%
33	त्रिपुरा	41,09,000	37,48,699	91.23%
34	उतार प्रदेश।	2332,97,000	2128,36,606	91.23%
35	उत्तराखंड	115,18,000	113,88,326	98.87%
36	पश्चिम बंगाल	986,04,000	940,01,541	95.33%
कुल		**13729,89,959**	**12778,86,750**	**93.07%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार

** दिनांक 02 नवंबर 21 के पत्र सीओएल/ आधार -जागरूकता/2021-22/3060 के माध्यम से डीडी और डीएनएच के यूटी प्रशासन कार्यालय से यथा प्राप्त अद्यतन की गई संशोधित जनसंख्या

** दिनांक 17.12.2021 के आरओ चंडीगढ़- आरओ सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी/2859 से यथा प्राप्त अद्यतन की गई चंडीगढ़ की गई संशोधित जनसंख्या
दिनांक 27.12.2021 के आरओ बेंगलुरू से प्राप्त अद्यतन की गई पुदुचेरी की संशोधित जनसंख्या

******